



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

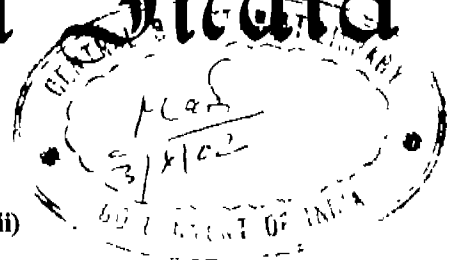
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 13]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2002/पौष 14, 1923

No. 13]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2002/PAUSA 14, 1923

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

का.आ. 16 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 999(अ) तारीख 26 नवम्बर, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, गुजरात राज्य तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- | | |
|---|---------|
| 1. प्रधान सचिव,
पर्यावरण और वन विभाग,
गुजरात सरकार। | अध्यक्ष |
| 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
गुजरात सरकार। | सदस्य |
| 3. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग,
गुजरात सरकार। | सदस्य |
| 4. मुख्य नगर योजनाकार,
गुजरात सरकार। | सदस्य |

- | | |
|--|------------|
| 5. प्रोफेसर निखिल देसाई,
महाराजा सयाजी राव
विश्वविद्यालय, बड़ौदा। | सदस्य |
| 6. प्रोफेसर अनिल गुप्ता,
इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ
मैनेजमेंट, अहमदाबाद। | सदस्य |
| 7. डा. शैलेस नायक, स्पेस
अप्लिकेशन सेंटर,
अहमदाबाद। | सदस्य |
| 8. निदेशक (पर्यावरण), वन और
पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार। | मदस्य-सचिव |

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

- तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजेडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।
- (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश

जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परन्तु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्यवाई करना।

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरण विवादों के संबंध में कार्यवाई करेगा जो उसे गुजरात राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिमहत्त्व क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अधिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो गुजरात के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकृत की जाती हैं।

X. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं।

XI. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

XII. प्राधिकरण की पूर्णगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय गांधी नगर में स्थित होगा।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-3]

डा. बी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS ORDER

New Delhi, the 4th January, 2002

S.O. 16 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number 999 (E) dated, the 26th November, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Gujarat State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

- | | |
|---|----------|
| 1. The Principal Secretary, | Chairman |
| Forests and Environment Department., | |
| Government of Gujarat. | |
| 2. The Principal Chief | Member |
| Conservator of Forests, | |
| Government of Gujarat. | |
| 3. The Principal Secretary | Member |
| Industries Department, | |
| Government of Gujarat. | |
| 4. The Chief Town Planner, | Member |
| Government of Gujarat. | |
| 5. Prof. Nikhil Desai, | Member |
| Maharaja Sayaji Rao University, Baroda. | |
| 6. Prof. Anil Gupta, | Member |
| Indian Institute of Management, | |
| Ahmedabad | |
| 7. Dr. Shailesh Nayak, | Member |
| Space Application Centre, | |
| Ahmedabad. | |

8. Director (Environment), Member-Secretary
Forests and Environment Department,
Government of Gujarat.

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of the State of Gujarat, namely:—

(i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Gujarat State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub-clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may either be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation.

(iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-clause (a) of sub-paragraph (ii) of paragraph II of the Order.

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Gujarat State Government, the National Coastal Zone

Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas

VI. The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification, of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O 144 (E) dated 19th February, 1991

IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Gujarat.

X. The Authority shall ensure that atleast two-third members of the Authority are present during the meetings.

XI. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

XII. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XIII. The Authority shall have its headquarters at Gandhinagar.

XIV. The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order

XV. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F.No 17011/18/96-IA-III]

DR. V RAJAGOPALAN, Jt. Secy

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

का.आ. 17 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 998(अ) तारीख 26 नवम्बर, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, दमण और दीव तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

1. प्रशासक, अध्यक्ष
दमण, द्वीप, दादरा और नागर हवेली,
सचिवालय, मोती दमन।
2. चीफ टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर, सदस्य
टाउन कन्ट्री प्लानिंग विभाग,
मोती दमण।
3. मुख्य वन संरक्षक, सदस्य
मोती दमण।
4. डॉ. शैलेस नायक, सदस्य
स्पेस अप्लिकेशन सेंटर,
अहमदाबाद।
5. विभागाध्यक्ष, सदस्य
पर्यावरणीय इंजिनियरिंग,
प्रादेशिक इंजिनियरिंग महाविद्यालय,
सूरत।
6. कलक्टर, सदस्य
दमण।
7. कलेक्टर, सदस्य
दीव।
8. सदस्य सचिव, सदस्य-सचिव
प्रदूषण नियंत्रण समिति,
मोती दमण।

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

- (i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

- (ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परन्तु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे।

- (iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

- (iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसंवेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन

मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो दमण और दीप के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं।

X. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं।

XI. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

XII. प्राधिकरण की पूर्वागामी शक्तियां और कृप्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय मोती दमण में स्थित होगा।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृष्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटारा जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-3]

डा. वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th January, 2002

S.O. 17 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number 998 (E) dated, the 26th November, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Daman and Diu Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

- | | |
|--|----------|
| 1. Administrator,
Daman and Diu,
Dadra and Nagar Haveli,
Secretariat, Moti Daman. | Chairman |
| 2. Chief Town and Country Planner,
Town Country Planning Department,
Moti Daman. | Member |
| 3. Chief Conservator of Forests,
Moti Daman. | Member |

- | | |
|---|------------------|
| 4. Dr. Shailesh Nayak,
Space Application Centre,
Ahmedabad. | Member |
| 5. Head of Department,
Environmental Engineering,
Regional Engineering College,
Surat. | Member |
| 6. Collector,
Daman. | Member |
| 7. Collector
Diu. | Member |
| 8. Member Secretary,
Pollution Control Committee,
Moti Daman. | Member-Secretary |

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of the Union Territory (U.T.) of Daman and Diu, namely:—

- (i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Daman and Diu Union Territory Administration and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.
 - (ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;
 - (b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority;
- Provided that the cases under sub-clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may either be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation.

- (iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-clause (a) of sub-paragraph (ii) of paragraph II of the Order.
- (iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.
- III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Union Territory, Daman and Diu, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.
- IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.
- V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas
- VI. The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.
- VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval
- VIII. The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification, of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide Number S O. 144 (E) dated 19th February, 1991.
- IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Daman and Diu.
- X. The Authority shall ensure that atleast two-third members of the Authority are present during the meetings.
- XI. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.
- XII. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
- XIII. The Authority shall have its headquarters at Moti Daman

- XIV. The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order.
- XV. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]

DR. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

का.आ. 18 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1003(अ) तारीख 26 नवम्बर, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्ण किया गया है या करने से लोप किया गया है, महाराष्ट्र राज्य तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- | | |
|---|---------|
| 1. प्रधान सचिव,
पर्यावरण विभाग,
महाराष्ट्र सरकार,
मुम्बई। | अध्यक्ष |
| 2. प्रधान सचिव,
राजस्व और वन विभाग,
महाराष्ट्र सरकार,
मुम्बई। | सदस्य |
| 3. प्रधान सचिव,
शहरी विकास,
महाराष्ट्र सरकार,
मुम्बई। | सदस्य |
| 4. डॉ. लीला भोंसले,
वनस्पति विभाग,
कोल्हापुर विश्वविद्यालय,
कोल्हापुर। | सदस्य |
| 5. श्री एस. अय्याप्पन,
निदेशक,
केन्द्रीय मीन शिक्षा संस्थान,
मुम्बई। | सदस्य |

6. श्री एस.के. गुप्ता, सदस्य
विभागाध्यक्ष,
सी.ई.एस.ई.,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
मुम्बई।

7. डॉ. श्रुतिकेश सामन्त, सदस्य
प्रवक्ता, प्राणी विज्ञान विभाग,
सेन्ट जेवियर्स कालेज,
मुम्बई।

8. सदस्य सचिव, सदस्य-सचिव
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड महाराष्ट्र
मुम्बई।

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा महाराष्ट्र राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परन्तु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए

उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्यवाई करना।

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्यवाई करेगा जो उसे महाराष्ट्र राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसंवेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अधिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो महाराष्ट्र के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं।

X. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं।

XI. प्राधिकरण उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

XII प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय मुम्बई में स्थित होगा।

XI. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा सं. 17011/18/96-आईए-3]

डा. बी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th January, 2002

S.O. 18 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number 1003 (E) dated, the 26th November, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Maharashtra State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely :—

- | | |
|--|------------------|
| 1. Principal Secretary,
Department of Environment,
Government of Maharashtra,
Mumbai. | Chairman |
| 2. Principal Secretary,
Department of Revenue and Forests,
Government of Maharashtra,
Mumbai. | Member |
| 3. Principal Secretary,
Urban Development,
Government of Maharashtra,
Mumbai. | Member |
| 4. Dr. Leela Bhosle,
Department of Botany,
Kolhapur University,
Kolhapur. | Member |
| 5. Mr. S. Ayyappan,
Director,
Central Institute of Fisheries Education,
Mumbai. | Member |
| 6. Mr. S.K. Gupta,
Head of the Department,
C.E.S.E.,
Indian Institute of Technology,
Mumbai. | Member |
| 7. Dr. Hrishikesh Samant,
Lecturer, Department of Zoology,
St. Xavier's College,
Mumbai. | Member |
| 8. Member Secretary,
Maharashtra Pollution Control Board,
Mumbai. | Member-Secretary |

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of the State of Maharashtra, namely :—

- (i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Maharashtra State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.
- (ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;
(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority :
Provided that the cases under sub-clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may either be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation.
- (iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-clause (a) of sub-paragraph (ii) of paragraph II of the Order.
- (iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.
- III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Maharashtra State Government the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.
- IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.
- V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas.

- VI. The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same
- VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval
- VIII. The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification, of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S O 144 (E) dated 19th February, 1991
- IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Maharashtra
- X. The Authority shall ensure that atleast two-third members of the Authority are present during the meetings
- XI. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority
- XII. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government
- XIII. The Authority shall have its headquarters at Mumbai
- XIV. The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order
- XV. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned

[F No 17011/18/96-IA-III]

DR V RAJAGOPALAN, Jt Secy

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

का.आ. 19(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं 995(अ) तारीख 26 नवम्बर, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें

ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, गोवा राज्य तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- | | |
|--|------------|
| 1. मुख्य सचिव,
गोवा सरकार। | अध्यक्ष |
| 2. सचिव,
पर्यावरण विभाग,
गोवा सरकार। | सदस्य |
| 3. वन संरक्षक,
गोवा सरकार। | सदस्य |
| 4. निदेशक, पर्यटन विभाग,
गोवा सरकार। | सदस्य |
| 5. डॉ. अरविन्द कंटावले,
भूतपूर्व राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान,
पंजिम। | सदस्य |
| 6. डा बी आर. सुब्रमण्यम,
निदेशक, एकीकृत तटीय और समुद्री
क्षेत्र प्रबंध,
(आईसीएमएएम)
महासागर प्रौद्योगिकी विभाग,
चेन्नई। | सदस्य |
| 7. श्री क्लादे अल्ब्वेरेस,
गोवा फाउन्डेशन, पंजिम। | सदस्य |
| 8. निदेशक और संयुक्त सचिव,
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग
गोवा सरकार। | सदस्य-सचिव |

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा गोवा राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

- (i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और गोवा राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।
- (ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों,

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परन्तु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरण विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे गोवा राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमृद्ध क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अधिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो गोवा के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकृत की जाती हैं।

X. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं।

XI. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

XII. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय पंजिम में स्थित होगा।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-3]

डा. बी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th January, 2002

S.O. 19 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number 995 (E) dated, the 26th November, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Goa State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

- | | |
|--|----------|
| 1. Chief Secretary, | Chairman |
| Government of Goa. | |
| 2. Secretary Dept. of Environment | Member |
| Government of Goa. | |
| 3. Conservator of Forests, | Member |
| Government of Goa. | |
| 4. Director, Department of Tourism, | Member |
| Government of Goa. | |
| 5. Dr. Arvind Untawale, | Member |
| Ex. National Institute of Oceanography, | |
| Panjim. | |
| 6. Dr. B.R. Subrahmanyam, | Member |
| Director, Integrated Coastal and Marine, | |
| Area Management (ICMAM), | |
| Department of Ocean Technology, | |
| Chennai. | |
| 7. Shri. Claude Alvares, | Member |
| Goa Foundation, Panjim. | |

8. Director and Joint Secretary, Member-Secretary
Department of Science, Tech-
nology and Environment.
Government of Goa.

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of the State of Goa, namely:—

(i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Goa State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority.

Provided that the cases under sub-clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may either be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation.

(iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-clause (a) of sub-paragraph (ii) of paragraph II of the Order.

(iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone

which may be referred to it by the Goa State the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification, of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 144 (E) dated 19th February, 1991.

IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Goa.

X. The Authority shall ensure that atleast two-third members of the Authority are present during the meetings

XI. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

XII. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XIII. The Authority shall have its headquarters at Panjim.

XIV. The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order.

XV. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]

DR. V. RAJAGOPALAN, Jt Secy

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

का.आ. 20(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1001(अ) तारीख 26 नवम्बर, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, केरल राज्य तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- | | |
|--|------------|
| 1. अध्यक्ष, एसटीईसी और पदेन प्रधान सचिव, एसटीईडी, केरल सरकार। | अध्यक्ष |
| 2. सचिव, मत्स्य विभाग, केरल सरकार। | सदस्य |
| 3. सचिव स्थानीय स्वशासन विभाग, केरल सरकार। | सदस्य |
| 4. सचिव, पर्यटन विभाग, केरल सरकार। | सदस्य |
| 5. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, केरल सरकार। | सदस्य |
| 6. डॉ. एम.बाबा. निदेशक, सेन्टर फार अर्थ साइंस स्टडीज, थिरुवनन्थपुरम। | सदस्य |
| 7. निदेशक, केन्द्रीय सामुद्रिक मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचीन। | सदस्य |
| 8. प्रोफसर एन. बालकृष्णन नायर, एमिरिटस साइंटिस्ट और भूतपूर्व अध्यक्ष, एसटीईसी। | सदस्य |
| 9. डॉ. एन.आर. मेनन, भूतपूर्व डीन, विज्ञान प्रभाग, सीयूएसएटी, कोचीन। | सदस्य |
| 10. निदेशक, एसटीईडी, केरल सरकार। | सदस्य-सचिव |

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्षालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा केरल राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय

प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और केरल राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परन्तु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे केरल राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो केरल के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं।

X. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं।

XI. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

XII. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय तिरुवनन्थपुरम में स्थित होगा।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित विधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-3]

डा. जी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th January, 2002

S.O. 20(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number 1001 (E) dated, the 26th November, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Kerala State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

- | | | |
|----|--|----------|
| 1 | Chairman, STEC and
Ex-officio Principal Secretary,
STED, Government of Kerala. | Chairman |
| 2. | Secretary, Department of Fisheries,
Government of Kerala | Member |

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 3. | Secretary, Department of Local Self Government, Government of Kerala. | Member |
| 4. | Secretary, Department of Tourism. | Member |
| 5. | Principal Secretary to Chief Minister, Government of Kerala. | Member |
| 6. | Dr. M. Baba, Director,
Centre for Earth Science Studies,
Thiruvananthapuram. | Member |
| 7. | Director, Central Marine Fisheries Research Institute, Cochin. | Member |
| 8. | Prof. N. Balakrishnan Nair,
Emeritus Scientist and Former
Chairman, STEC. | Member |
| 9. | Dr. N.R. Menon, Former Dean,
Sciences Division, CUSAT, Cochin. | Member |
| 10. | Director, STED,
Government of Kerala. | Member-Secretary |

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of the State of Kerala namely:—

(i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Kerala State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

(ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority;

Provided that the cases under sub-clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may either be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an

- individual or a representative body or an organisation.
- (iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-clause (a) of sub-paragraph (ii) of paragraph II of the Order.
- (iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order
- III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Kerala State Government the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.
- IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.
- V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas
- VI. The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.
- VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.
- VIII. The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 144 (E) dated 19th February, 1991.
- IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Kerala.
- X. The Authority shall ensure that atleast two-third members of the Authority are present during the meetings.
- XI. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.
- XII. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

- XIII. The Authority shall have its headquarters at Thiruvananthapuram
- XIV. The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order.
- XV. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]

DR. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

का.आ. 21(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1000(अ) तारीख 26 नवम्बर, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, कर्नाटक राज्य तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- | | |
|---|---------|
| 1. प्रधान सचिव,
पर्यावरण और वन विभाग,
कर्नाटक सरकार। | अध्यक्ष |
| 2. निदेशक,
उद्योग विभाग,
कर्नाटक सरकार। | सदस्य |
| 3. अध्यक्ष,
कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
कर्नाटक सरकार। | सदस्य |
| 4. फादर सी.जे. सल्दान्हा,
भूतपूर्व निदेशक, टेक्सोनोमिक स्टडीज,
वनस्पति विज्ञान,
सेंट जोसेफ कालेज, बेंगलूर। | सदस्य |
| 5. श्री प्रणबस सन्याल,
मुख्य वन संरक्षक,
पश्चिमी बंगाल सरकार, कोलकाता। | सदस्य |
| 6. निदेशक,
मत्स्य विभाग,
कर्नाटक सरकार,
बेंगलूर। | सदस्य |

7. डॉ. एच. होन्ने गौडा,
निदेशक,
कर्नाटक रिमोट सेन्सिंग यूनिट,
बैंगलोर।

सदस्य

उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्यवाई करना।

8. मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक कार्यालय,
पर्यावरण और वन मंत्रालय,
केन्द्रीय सदन, कोरामंगला,
बैंगलोर।

सदस्य

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्यवाई करेगा जो उसे कर्नाटक राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

9. निदेशक,
पर्यावरण तकनीकी प्रकोष्ठ,
वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग,
कर्नाटक सरकार।

सदस्य-सचिव

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमृद्ध क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा कर्नाटक राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

VIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अधिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 144(अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा।

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो कर्नाटक के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं।

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

X. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं।

XI. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

परन्तु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे।

XII. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय बैंगलोर में स्थित होगा।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-3]

डा. बी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th January, 2002

S.O. 21(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number 1000 (E) dated, the 26th November, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Karnataka State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

- | | |
|--|------------------|
| 1. Principal Secretary,
Department of Environment and Forests,
Government of Karnataka | Chairman |
| 2. Director,
Department of Industries,
Government of Karnataka. | Member |
| 3. Chairman,
Karnataka State Pollution
Control Board, Government of Karnataka , | Member |
| 4. Father C.J. Saldhana,
Ex-Director, Taxonomic Studies,
Department of Botany,
St. Joseph's College, Bangalore. | Member |
| 5. St. Pranabes Sanyal,
Chief Conservator of Forests,
Government of West Bengal, Kolkata. | Member |
| 6. Director,
Department of Fisheries,
Government of Karnataka,
Bangalore. | Member |
| 7. Dr. H. Honne Gowda,
Director,
Karnataka Remote Sensing Unit,
Bangalore. | Member |
| 8. Chief Conservator of Forests,
Regional Office,
Ministry of Environment and Forests,
Kendriya Sadan, Koramangala,
Bangalore. | Member |
| 9. Director,
Environment Technical Cell,
Department of Forest, Ecology and
Environment,
Government of Karnataka. | Member-Secretary |

- II The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and

controlling environmental pollution in the coastal areas of the State of Karnataka namely:—

- (i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Karnataka State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.
 - (ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under Section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;
(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority;
Provided that the cases under sub-clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may either be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation.
 - (iii) Filing complaints under Section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-clause (a) of sub-paragraph (ii) of paragraph II of the Order.
 - (iv) To take action under Section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.
- III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Karnataka State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.
- IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

- V The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas
- VI The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same
- VII The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval
- VIII The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification, of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S O 144 (E) dated 19th February, 1991
- IX The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Karnataka
- X The Authority shall ensure that atleast two-third members of the Authority are present during the meetings
- XI The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority
- XII The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government
- XIII The Authority shall have its headquarters at Bangalore
- XIV The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order
- XV Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned

[F No 17011/18/96-IA-III]

DR V RAJAGOPALAN, Jt Secy

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

का.आ. 22(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त

अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 996(अ) तारीख 26 नवम्बर, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, पांडिचेरी राज्य तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् —

- | | |
|--|------------|
| 1 सचिव,
पर्यावरण विभाग,
पांडिचेरी सरकार। | अध्यक्ष |
| 2 निदेशक,
मत्स्य विभाग,
पांडिचेरी। | सदस्य |
| 3. मुख्य नगर योजनाकार,
नगर और देशीय योजना विभाग। | सदस्य |
| 4. डॉ. आर.एल. महादेवन,
राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
चेन्नई। | सदस्य |
| 5 डॉ एल कानन,
निदेशक, सेन्ट्रल फार एडवांस स्टडीज इन मैरीन,
बाईलोजी,
चेन्नई। | सदस्य |
| 6 डॉ. एम रविन्द्रन,
निदेशक,
समुद्र विकास विभाग,
चेन्नई। | सदस्य |
| 7. सदस्य सचिव,
पांडिचेरी प्रदूषण नियंत्रण समिति,
पांडिचेरी। | सदस्य-सचिव |

II प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पांडिचेरी राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

- (i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और पांडिचेरी राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।
- (ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक

प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परन्तु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे पांडिचेरी राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमृद्ध क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो पांडिचेरी के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं।

X. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं।

XI. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

XII. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय पांडिचेरी में स्थित होगा।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-3]

डा. बी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th January, 2002

S.O. 22(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number 996 (E) dated, the 26th November, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Pondicherry Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

- | | |
|--|----------|
| 1. Secretary,
Department of Environment,
Pondicherry. | Chairman |
| 2. Director,
Department of Fisheries,
Pondicherry. | Member |
| 3. Chief Town Planner,
Town and Country Planning Department. | Member |
| 4. Dr. R. Mahadevan,
National Institute of Ocean Technology,
Indian Institute of Technology,
Chennai. | Member |
| 5. Dr L. Kannan,
Director,
Centre for Advanced Studies in
Marine Biology,
Annamalai University | Member |

6. Dr. M. Ravindran, Member
Director,
Department of Ocean Development,
Chennai.
7. Member Secretary, Member-Secretary
Pondicherry Pollution Control
Committee, Pondicherry.

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of the State of Pondicherry namely:—

- (i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Pondicherry State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.
- (ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;
(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:
Provided that the cases under sub-clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may either be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation.
- (iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-clause (a) of sub-paragraph (ii) of paragraph II of the Order.
- (iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

- III The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Pondicherry State Government the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.
- IV The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.
- V The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas.
- VI The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.
- VII The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.
- VIII The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification, of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 144 (E) dated 19th February, 1991.
- IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Pondicherry.
- X. The Authority shall ensure that atleast two-third members of the Authority are present during the meetings.
- XI. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority
- XII. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
- XIII. The Authority shall have its headquarters at Pondichery.
- XIV. The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order.
- XV. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F No. 17011/18/96-IA-III]

Dr. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

का.आ. 23 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 994(अ) तारीख 26 नवम्बर, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्ण किया गया है या करने से लोप किया गया है, तमिलनाडु राज्य तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- | | |
|--|------------|
| 1. सरकार के सचिव,
पर्यावरण और वन विभाग,
तमिलनाडु सरकार। | अध्यक्ष |
| 2. निदेशक,
नगर और देशीय योजना,
तमिलनाडु सरकार,
चेन्नई। | सदस्य |
| 3. डा. एम. रविन्द्रन,
निदेशक,
राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान,
चेन्नई। | सदस्य |
| 4. एस. रामचन्द्रन,
निदेशक,
समुद्र प्रबंध संस्थान,
चेन्नई। | सदस्य |
| 5. डा. एल. कानन,
परियोजना निदेशक,
सेन्ट्रल फार एडवांस स्टडीज इन
मैरीन बाईलोजी,
अन्नामलाई विश्वविद्यालय | सदस्य |
| 6. प्रादेशिक निदेशक,
केन्द्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड,
चेन्नई। | सदस्य |
| 7. सदस्य—सचिव
तमिलनाडु प्रदूषण बोर्ड,
चेन्नई-32। | सदस्य |
| 8. पर्यावरण निदेशक,
तमिलनाडु सरकार,
चेन्नई। | सदस्य-सचिव |

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा तमिलनाडु राज्य के तटीय क्षेत्रों में

पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परन्तु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरण विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे तमिलनाडु राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसंवेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अधिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144(अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो तमिलनाडु के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं।

X. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं।

XI. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

XII प्राधिकरण की पूर्वागामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में स्थित होगा।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-3]

डा. बी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th January, 2002

S.O. 23 (E).— In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number 994(E) dated, the 26th November, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Tamil Nadu State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | The Secretary of Government
Environment and Forests Department,
Government of Tamil Nadu. | Chairman |
|---|---|----------|

- | | | |
|----|--|------------------|
| 2. | The Director of Town and
Country Planning,
Government of Tamil Nadu,
Chennai. | Member |
| 3. | Dr. M. Ravindran,
Director,
National Institute of Ocean Technology,
Chennai. | Member |
| 4. | Dr. S. Ramachandran,
Director,
Institute of Ocean Management
Chennai | Member |
| 5. | Dr. L. Kannan,
Project Director,
Centre for Advanced Studies
in Marine Biology,
Annamalai University | Member |
| 6 | Regional Director
Central Ground Water Board,
Chennai. | Member |
| 7. | Member—Secretary,
Tamil Nadu Pollution Board,
Chennai-32. | Member |
| 8. | The Director of Environment,
Government of Tamil Nadu,
Chennai. | Member-Secretary |

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of the State of Tamil Nadu, namely:—

- (i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Tamil Nadu, State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.
- (ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;
- (b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and

the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub-clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may either be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation.

- (iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-clause (a) of sub-paragraph (ii) of paragraph II of the Order.
- (iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.
- III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Tamil Nadu State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.
- IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.
- V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas.
- VI. The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same
- VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.
- VIII. The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification, of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 144 (E) dated 19th February, 1991.
- IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid

down in the approved Coastal Zone Management Plan of Tamil Nadu.

- X. The Authority shall ensure that atleast two-third members of the Authority are present during the meetings.
- XI. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.
- XII. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
- XIII. The Authority shall have its headquarters at Chennai.
- XIV. The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order.
- XV. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]

DR. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

का.आ. 24 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1004(अ) तारीख 26 नवम्बर, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, उड़ीसा राज्य तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

1. प्रधान सचिव, अध्यक्ष
वन और पर्यावरण,
उड़ीसा सरकार।
2. मुख्य वन संरक्षक, सदस्य
क्षेत्रीय कार्यालय,
पर्यावरण और वन मंत्रालय,
भुवनेश्वर।
3. प्रधान सचिव, सदस्य
शहरी विकास विभाग,
उड़ीसा सरकार।

4. डा. बी.आर. सुब्रह्मण्यम, सदस्य
निदेशक, एकीकृत तटीय और
सामुद्रिक क्षेत्र प्रबंध,
समुद्र विकास विभाग,
चेन्नई।

5. मुख्य कार्यपालक, सदस्य
खिलका विकास प्राधिकरण और
उड़ीसा सरकार।

6. श्री प्रणबस सन्ताल, सदस्य
मुख्य वन संरक्षक,
पश्चिमी बंगाल सरकार।

7. प्रोफेसर ए.बी. रमण, सदस्य
विभागाध्यक्ष,
प्राणी विज्ञान और समुद्री विज्ञान।

8. निदेशक, सदस्य-सचिव
पर्यावरण विभाग, उड़ीसा सरकार।

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा उड़ीसा राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परन्तु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुपालन

के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरण विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे उड़ीसा राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमैद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अधिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144(अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो उड़ीसा के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं।

X. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं।

XI. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

XII प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्प केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित होगा।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-3]

डॉ. वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th January, 2002

S.O. 24 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number 1004 (E) dated, the 26th November, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Orissa State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

- | | |
|--|------------------|
| 1. Principal Secretary,
Forests and Environment,
Government of Orissa. | Chairman |
| 2. Chief Conservator of Forests
Regional Office,
Ministry of Environment and Forests,
Bhubaneswar. | Member |
| 3. Principal Secretary
Department of Urban Development,
Government of Orissa. | Member |
| 4. Dr. B.R. Subrahmaniam,
Director, Iterated Coastal and Marine
Area Management,
Deptt. of Ocean Development,
Chennai. | Member |
| 5. Chief Executive,
Chilka Development Authority &
Government of Orissa. | Member |
| 6. Shri Pranabes Sanyal,
Chief Conservator of Forests,
Government of West Bengal. | Member |
| 7. Prof. A. V. Raman,
Head of Department,
Department of Zoology and
Marine Science. | Member |
| 8. Director
Department Environment
Government of Orissa. | Member-Secretary |

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of the State of Orissa, namely:—

- (i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Orissa State Government and making specific recommendations to the National

Coastal Zone Management Authority therefor

- (ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act, or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government,
- (b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:
- Provided that the cases under sub-clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may either be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation.
- (iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-clause (a) of sub-paragraph (ii) of paragraph II of the Order.
- (iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.
- III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Orissa State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.
- IV The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.
- V The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas.
- VI. The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.
- VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and

- modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.
- VIII. The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 144 (E) dated 19th February, 1991.
- IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Orissa.
- X. The Authority shall ensure that atleast two-third members of the Authority are present during the meetings.
- XI. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.
- XII. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
- XIII. The Authority shall have its headquarters at Bhubaneswar.
- XIV. The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order.
- XV. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F.No. 17011/18/96-IA-III]

DR. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

का.आ. 25 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 997(अ) तारीख 26 नवम्बर, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, पश्चिमी बंगाल राज्य तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि

के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- | | |
|--|------------|
| 1. प्रधान सचिव,
पर्यावरण विभाग,
पश्चिमी बंगाल सरकार। | अध्यक्ष |
| 2. प्रधान सचिव,
वन विभाग,
पश्चिमी बंगाल सरकार। | सदस्य |
| 3. निदेशक,
मत्स्य विभाग,
पश्चिमी बंगाल सरकार। | सदस्य |
| 4. सदस्य सचिव,
पश्चिमी बंगाल प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड। | सदस्य |
| 5. श्री प्रणबस सन्ध्याल,
मुख्य वन संरक्षक,
पश्चिमी बंगाल सरकार। | सदस्य |
| 6. प्रोफेसर सुगाता हाजरा,
भू-विज्ञान विभाग,
जादवपुर विश्वविद्यालय। | सदस्य |
| 7. निदेशक,
सुन्दरवन विकास प्राधिकरण,
पश्चिमी बंगाल सरकार। | सदस्य |
| 8. निदेशक,
पर्यावरण विभाग,
पश्चिमी बंगाल सरकार। | सदस्य-सचिव |

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पश्चिमी बंगाल राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

- (i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।
- (ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;
- (ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का

पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परन्तु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों में संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमृद्ध क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो पश्चिमी बंगाल के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकृत की जाती हैं।

X. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं।

XI. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

XII प्राधिकरण की पूर्णगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित होगा।

XI. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-3]

डा. श्री. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th January, 2002

S.O. 25 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number 997(E) dated, the 26th November, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the West Bengal State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely —

1	Principal Secretary, Department of Environment, Government of West Bengal	Chairman
2	Principal Secretary, Department of Forests, Government of West Bengal	Member
3	Director, Fisheries Department, Government of West Bengal	Member
4	Member Secretary, West Bengal Pollution Control Board.	Member
5	Shri Pranabes Sanyal Chief Conservator of Forests, Government of West Bengal.	Member
6	Prof. Sugata Hazara, Department of Zoology, Jadavpur University.	Member
7	Director, Sunderbans Development Authority, Government of West Bengal.	Member
8.	Director Department Environment Government of West Bengal.	Member-Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and

controlling environmental pollution in the coastal areas of the State of West Bengal namely :—

- (i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the West Bengal State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.
- (ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act, or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government,
(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:
Provided that the cases under sub-clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may either be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation
- (iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-clause (a) of sub-paragraph (ii) of paragraph II of the Order.
- (iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.
- III The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the West Bengal State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government
- IV The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas

- V The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas
- VI The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same
- VII The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.
- VIII The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification, of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S O 144 (E) dated 19th February, 1991
- IX The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of West Bengal
- X The Authority shall ensure that atleast two-third members of the Authority are present during the meetings
- XI The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.
- XII The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government
- XIII The Authority shall have its headquarters at Kolkata
- XIV The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order.
- XV Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F No 17011/18/96-IA-III]

DR. V RAJAGOPALAN, Jt. Secy

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

का.आ. 26(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसका पश्चात् उक्त

अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1002(अ) तारीख 26 नवम्बर, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

1. प्रशासक सह-सचिव, अध्यक्ष
(पर्यावरण और वन),
लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र,
कावारति।
2. उप वन संरक्षक, सदस्य
कावारति।
3. अधीक्षण इंजीनियर, सदस्य
लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग,
कावारति।
4. डा. एम.बाबा, सदस्य
निदेशक या उनके प्रतिनिधि,
सेंटर फार अर्थ साइंस स्टडीज,
थिरुवानन्थपुरम।
5. निदेशक, सदस्य
केन्द्रीय सामुद्रिक,
मत्स्य अनुसंधान मंस्थान,
कोच्चि।
6. मुख्य इंजीनियर और प्रशासक, सदस्य
अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म,
जल, भूतल परिवहन मंत्रालय,
पोर्ट ब्लेयर।
7. सदस्य-सचिव, सदस्य-सचिव
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लक्षद्वीप।

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

- (i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।
- (ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की

जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परन्तु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरण विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमैद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अधिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के

- अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा।
- IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो लक्षद्वीप के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं।
- X. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं।
- XI. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
- XII. प्राधिकरण की पूर्वागामी शक्तियां और कृत्प केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।
- XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय कावारति में स्थित होगा।
- XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्पों को करने के लिए उपबंधित विधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा।
- XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटारा जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-3]

डॉ. वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th January, 2002

S.O. 26 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number 1002 (E) dated, the 26th November, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

- | | |
|---|----------|
| 1. Administrator cum Secretary,
(Environment and Forests),
Union Territory of Lakshadweep,
Kavarati. | Chairman |
| 2. Deputy Conservator of Forests,
Kavarati. | Member |
| 3. Superintending Engineer,
Lakshadweep Public Works Department,
Kavarati. | Member |
| 4. Dr. M. Baba,
Director or his representative,
Centre for Earth Sciences Studies,
Thiruvananthapuram. | Member |

- | | |
|--|------------------|
| 5. Director,
Central Marine Fisheries,
Research Institute,
Cochin. | Member |
| 6. Chief Engineer and Administrator,
Andaman Lakshadweep,
Harbour, Works,
Ministry of Surface Transport,
Port Blair. | Member |
| 7. Member Secretary,
Pollution Control Board,
Lakshadweep. | Member-Secretary |

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of the Union Territory of Lakshadweep, namely:—

- (i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Lakshadweep Union Territory Administration and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

- (ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority;

Provided that the cases under sub-clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may either be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation.

- (iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the

- directions issued by it under sub-clause (a) of sub-paragraph (ii) of paragraph II of the Order.
- (iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.
- III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Lakshadweep Union Territory Administration, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.
- IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.
- V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas.
- VI. The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.
- VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval
- VIII. The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification, of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S O. 144 (E) dated 19th February, 1991.
- IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Lakshadweep.
- X. The Authority shall ensure that atleast two-third members of the Authority are present during the meetings.
- XI. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.
- XII. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
- XIII. The Authority shall have its headquarters at Kavarathi.
- XIV. The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order.
- XV. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F.No 17011/18/96-IA-III]

DR. V RAJAGOPALAN, Jt. Secy

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

का.आ. 27(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 993(अ) तारीख 26 नवम्बर, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, आन्ध्र प्रदेश राज्य तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- | | |
|---|---------|
| 1. प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन और विज्ञान
तथा प्रौद्योगिकी,
आन्ध्र प्रदेश सरकार,
हैदराबाद। | अध्यक्ष |
| 2. सचिव,
राजस्व विभाग,
आन्ध्र प्रदेश सरकार,
हैदराबाद। | सदस्य |
| 3. निदेशक,
नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी,
हैदराबाद। | सदस्य |
| 4. प्रो. डी. सत्यनारायण,
कोमैप्स, महासागर विकास विभाग,
प्लॉट सं. 51, पांडुरंगपुरम,
विशाखापत्तनम। | सदस्य |
| 5. प्रो. ए.बी. रमण,
प्राणि विज्ञान और समुद्री जीव
विज्ञान विभाग,
आन्ध्र प्रदेश विश्वविद्यालय,
विशाखापत्तनम। | सदस्य |

6. सदस्य-सचिव, आन्ध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवासीय और शहरी विकास प्राधिकरण काम्पलेक्स, हैदराबाद। सदस्य
7. डा. सुब्रामण्यम् निदेशक, इंटीग्रेटेड कोस्टल एण्ड मैरिन एरिया मैनेजमेंट, महासागर विकास समिति, चेन्नई। सदस्य
8. निदेशक, तटक्षेत्र विकास प्राधिकरण, हैदराबाद। सदस्य-सचिव

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा आंध्र प्रदेश राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

- (i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।
- (ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;
- (ख) उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परन्तु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निष्पक्ष या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे।

- (iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।
- (iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरण विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमैद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144(अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो आंध्र प्रदेश के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं।

X. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं।

XI. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

XII. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित होगा।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटारा जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-3]

डा. बी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th January, 2002

S.O. 27(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to

as the said Act), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number 993(E) dated, the 26th November, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Andhra Pradesh State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

- | | |
|---|------------------|
| 1. Principal Secretary,
Environment, Forests and
Sciences and Technology,
Government of Andhra Pradesh,
Hyderabad. | Chairman |
| 2. Secretary,
Department of Revenue,
Government of Andhra Pradesh,
Hyderabad. | Member |
| 3. Director,
National Remote Sensing Agency,
Hyderabad. | Member |
| 4. Prof. D. Satyanarayanan,
COMAPS, Department of Ocean,
Development, Plot No. 51,
Pandurangapuram,
Visakhapatnam. | Member |
| 5. Prof. A. V. Raman,
Department of Zoology and Marine Biology,
Andhra Pradesh University,
Visakhapatnam. | Member |
| 6. Member Secretary,
Andhra Pradesh Pollution Control,
Board, Housing and Urban Development,
Authority Complex,
Hyderabad. | Member |
| 7. Dr. B.R. Subrahmaniam,
Director, Integrated Coastal and Marine,
Area Management,
Department of Ocean Development,
Chennai. | Member |
| 8. Director,
Shore Area Development Authority,
Hyderabad. | Member-Secretary |

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of the State of Andhra Pradesh, namely:—

- (i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Andhra

Pradesh, State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.

- (ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority;

Provided that the cases under sub-clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may either be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation.

- (iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-clause (a) of sub-paragraph (ii) of paragraph II of the Order.
- (iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Andhra Pradesh State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

- VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.
- VIII. The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification, of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O 144 (E) dated 19th February, 1991.
- IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Andhra Pradesh.
- X. The Authority shall ensure that atleast two-third members of the Authority are present during the meetings.
- XI. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority
- XII. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
- XIII. The Authority shall have its headquarters at Hyderabad.
- XIV. The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order.
- XV. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F No 17011/18/96-IA-III]

DR. V RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

का.आ. 28(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 992(अ) तारीख 26 नवम्बर, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्ण किया गया है या करने से लोप किया गया है, अंदमान और निकोबार द्वीप तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति

होंगे, अर्थात् :—

- | | |
|--|------------|
| 1. मुख्य सचिव,
अंदमान और निकोबार द्वीप प्रशासन,
अंदमान और निकोबार द्वीप,
पोर्ट ब्लेयर। | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य इंजीनियर और प्रशासक,
अंदमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म,
जल भूतल परिवहन मंत्रालय,
पोर्ट ब्लेयर। | सदस्य |
| 3. सचिव,
पर्यावरण विभाग,
अंदमान और निकोबार द्वीप,
पोर्ट ब्लेयर। | सदस्य |
| 4. निदेशक,
मत्स्य विभाग,
पोर्ट ब्लेयर। | सदस्य |
| 5. डॉ. एस. रामाचन्द्रन,
निदेशक,
समुद्र प्रबंध संस्थान,
चेन्नई। | सदस्य |
| 6. डॉ. पी. एस. एन. राव,
भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण,
पोर्ट ब्लेयर। | सदस्य |
| 7. वन संरक्षक,
अंदमान और निकोबार द्वीप,
पोर्ट ब्लेयर। | सदस्य-सचिव |

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा अंदमान और निकोबार द्वीप संघ के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

- (i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट मिफारिशें करना।
- (ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परन्तु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निःशुल्क या किसी संगठन द्वारा की गई शिक्षा के आधार पर लिये जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए विदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरण विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे अंदमान और निकोबार द्वीप संघ सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमृद्ध क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो अंदमान और निकोबार द्वीप के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकृत की जाती हैं।

X. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं।

XI. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

XII. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में स्थित होगा।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-3]

डा. बी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th January, 2002

S.O. 28(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number 992(E) dated, the 26th November, 1998, expect as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Andaman and Nicobar Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely—

- | | |
|--|------------------|
| 1. Chief Secretary, | Chairman |
| Andaman and Nicobar Administration, | |
| Andaman and Nicobar Islands, | |
| Port Blair. | |
| 2. Chief Engineer & Administrator, | Member |
| Andaman and Lakshadweep Harbour Works, | |
| Ministry of Surface Transport, | |
| Port Blair. | |
| 3. Secretary, | Member |
| Department of Environment, | |
| Andaman and Nicobar, | |
| Port Blair. | |
| 4. Director, | Member |
| Department of Fisheries, | |
| Port Blair. | |
| 5. Dr S. Ramachandran, | Member |
| Director, | |
| Institute of Ocean Management, | |
| Chennai. | |
| 6. Dr P. S. N. Rao, | Member |
| Botanical Survey of India, | |
| Port Blair. | |
| 7. Conservator of Forests, | Member-Secretary |
| Andaman and Nicobar Islands, | |
| Port Blair | |

- II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas of the Union Territory of Andaman and Nicobar, namely:—
- (i) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the of Andaman and Nicobar Union Territory Administration and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor.
 - (ii) (a) Inquire into cases of alleged violations of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;
(b) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act, and the rules made thereunder, or under any other law which is related to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority.
Provided that the cases under sub-clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may either be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation.
 - (iii) Filing complaints under section 19 of the said Act in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-clause (a) of sub-paragraph (ii) of paragraph II of the Order
 - (iv) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.
- III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Andaman and Nicobar Union Territory Administration
- the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.
- IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas
 - V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area specific management plans for such identified areas.
 - VI. The Authority shall identify economically important stretches in Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.
 - VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval
 - VIII. The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification, of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 144 (E) dated 19th February, 1991.
 - IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are stipulated and laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Andaman and Nicobar.
 - X. The Authority shall ensure that atleast two-third members of the Authority are present during the meetings.
 - XI. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority
 - XII. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
 - XIII. The Authority shall have its headquarters at Port Blair.
 - XIV. The Authority shall open an account in any of the nationalized banks in the name of the Authority for the purpose of receiving funds provided for undertaking the activities and functions listed in this order.
 - XV. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 17011/18/96-IA-III]

DR. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

